

जलवायु परिवर्तन के एजेंडे को सुरक्षित करने के प्रयास के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन पर एक मसौदा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत का नकारात्मक वोट, यूएनएससी के जनादेश को उन क्षेत्रों में विस्तारित करने के अपने लंबे समय के विरोध का प्रतिबिंब है जो पहले से ही अन्य बहु-राष्ट्रीय मंचों द्वारा निपटाए जा रहे हैं।

संकल्प, आयरलैंड और नाइजर द्वारा संचालित था और जिसे यूएनएससी के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, भारत और रूस द्वारा नकारात्मक मतदान किया गया था। जबकि चीन ने भाग नहीं लिया। रूस ने इस पर अपना वीटो भी लगाया। उनकी स्थिति यह है कि UNSC की प्राथमिक जिम्मेदारी "अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना" है और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे इसके दायरे से बाहर हैं।

लेकिन प्रस्ताव के समर्थकों का तर्क है कि जलवायु दुनिया में सुरक्षा जोखिम पैदा कर रही है, जो भविष्य में पानी की कमी, प्रवास और आजीविका के विनाश के साथ बढ़ेगी। जर्मनी ने पिछले साल इसी तरह का एक मसौदा जारी किया था जिसे सुरक्षा परिषद में कभी भी मतदान के लिए नहीं रखा गया था क्योंकि ट्रम्प प्रशासन ने इसका विरोध किया था। अब, बिडेन प्रशासन के समर्थन से, विकसित दुनिया यूएनएससी के एजेंडे में "जलवायु सुरक्षा" को शामिल करने पर जोर दे रही है।

जबकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई करने की तात्कालिकता की सराहना की जाती है, जलवायु एजेंडे को सुरक्षित करने के प्रयास के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। इस मुद्दे को यूएनएससी के तहत लाने से दुनिया के औद्योगिक देशों को, जो वीटो पावर रखते हैं, जलवायु संबंधी सुरक्षा मुद्दों पर भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान करेंगे।

वर्तमान में, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC), एक विशेष एजेंसी में चर्चा की जा रही है और 190 से अधिक सदस्यों के साथ, इसके ढांचे ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति की है। इसी प्रक्रिया के कारण क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और हाल ही में COP26 शिखर सम्मेलन हुआ और इसने वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्थापित किया है। निश्चित रूप से, मान्य आलोचना है कि यूएनएफसीसीसी सम्मेलनों में निर्णय लेना धीमा है और जलवायु परिवर्तन और संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए तेजी से सामूहिक कार्रवाई होनी चाहिए।

लेकिन समाधान यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्यों को निर्णय लेने की आउटसोर्सिंग करना नहीं हो सकती है। साथ ही जलवायु परिवर्तन को सुरक्षा के चश्मे से देखना गलत है। हर देश को हरित अर्थव्यवस्था में बदलने में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, विकसित देश, सभी बड़े प्रदूषक, जलवायु कार्रवाई के संबंध में किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं। कम से कम विकसित और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता से किए गए वादों को निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह एक सामूहिक प्रक्रिया होनी चाहिए और सबसे अच्छा तरीका यूएनएफसीसीसी के माध्यम से है, जहाँ किए गए निर्णय आम सहमति से होते हैं।

यूएनएफसीसीसी को न केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सदस्य देशों, विशेष रूप से शक्तिशाली देशों द्वारा, पिछले सम्मेलनों में किए गए वादों को पूरा किया जाए, बल्कि जलवायु संबंधी सुरक्षा मुद्दों को शामिल करने के लिए चर्चा के दायरे का विस्तार भी किया जाए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

- प्र. हाल ही में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में नकारात्मक वोटिंग की?
- (a) आतंकवाद
(b) जलवायु परिवर्तन
(c) शरणार्थी संकट
(d) उपर्युक्त सभी।

Expected Question (Prelims Exams)

- Q. Recently, on which of the following issues did India get negative voting in the Security Council of the United Nations?
- (a) Terrorism
(b) Climate change
(c) Refugee crisis
(d) All of the above.

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

- प्र. जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाना कहाँ तक उचित है? साथ ही यह भी बताइए भारत का इस पर अपनाया गया रुख कितना तार्किक है? (250 शब्द)
- Q. To what extent is it appropriate to bring a resolution in the United Nations Security Council regarding climate change? Also tell how logical is the stand adopted by India on this? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।